सैंट्रल चीन और तिब्बत के बीच वैस्टर्न शिचुआन प्रांत में सैंकडों रहस्यमय स्टोन टावर्स हैं, इनमें से कुछ तो 200 फीट तक ऊँचे हैं। हिमालय की तलहटी में ऐसे टावर बड़ी तादाद में हैं और गांवों के समीप ज्यादा देखे जाते हैं, जहां अब याक और टट्टुओं के अस्तबल के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। ये सदियों से यहाँ हैं, पर इनके निर्माण का उद्गम और उद्देश्य दोनों ही हमेशा से रहस्यमय रहा है, स्थानीय लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। बाहरी दुनिया को टावर के बारे में सबसे पहले फ्रांस की खोजी यात्री फ्रैडरीक डरागॉन ने बताया था। वह 1998 में स्नो लैपर्ड की खोज में तिब्बत गयी थी, लेकिन उसका ध्यान खींचा इन रहस्यमय इमारतों ने। अगले 5 साल तक उसने इन मीनारों की गणना और नाप जोख की, तस्वीरें लीं और टावर पर चढ़कर इसकी बीम की लकड़ी के सैम्पल लिए। लेकिन, किसी को भी पता नहीं था कि टावर्स किसने और क्यों बनाए थे। तथापि, उन्नीसवीं सदी में चीन आए यूरोपीय यात्रियों की डायरियों कुछ चीनी आख्यानों में उसे इन टावर्स का कुछ उल्लेख अवश्य मिला। डरागॉन का मानना है कि, टावर्स के उद्गम के बारे में स्थानीय जानकारी के अभाव का कारण क्षेत्र का इतिहास और भूगोल हो सकता है। जिस क्षेत्र में ये टावर हैं वहाँ कई पहाड़ी जनजातियाँ रहती हैं जिन्होंने सदियों से अपने आप को "आइसोलेशन" में रखा है। इनकी बोली, रीति रिवाज, रहन-सहन, हर तरह से एक दूसरे से बहुत अलग हैं। डरागॉन की डॉक्युमैंटरी, "सीक्रेट टावर्स ऑफ हिमालय" के अनुसार "एक घाटी से दूसरी घाटी के लोग एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर पाते।" डरागॉन का मानना है कि, टावर्स का इतिहास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मौखिक रूप से बताया गया होगा, लेकिन अब लोग इन्हें भूल गए हैं। टावर की लकड़ी की रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये 600 से 1000 साल पुराने हैं। डरागॉन का मानना है कि, टावरों की डिजाइन की भिन्नता को देखते हुए लगता है कि, अलग-अलग क्षेत्रों में इनका उपयोग अलग-अलग उद्देश्यों के लिए होता होगा। उदाहरण के लिए मिनिआक क्षेत्र में टावर निगरानी के लिए काम आते होंगे। कॉन्गपो और डम्बा के टावर समृद्धि और गौरव का प्रतीक लगते हैं। एक कहानी के अनुसार, मंगोल शासित चीन के साथ व्यापार करके अमीर बने स्थानीय लोगों ने कई टावर बनवाए थे। फ्रैडरीक डरागॉन टावर्स को युनैस्को वर्ल्ड हैरिटेज साइट में शामिल करवाने के लिए प्रयास कर रही हैं।

जाट वोट बैंक को रिझाने के लिए वीर तेजा कल्याण बोर्ड का गठन

पर क्या सिर्फ बोर्ड का गठन करके जाट समाज को कांग्रेस साध पाएगी, इसमें संशय नजर आता है

- **जाट महाकुंभ से पहले बोर्ड का गठन किया गया है, लेकिन समाज की प्रमुख मांग तो ओ.बी.सी. की जातियों में वर्गीकरण की है।**
- **वैसे भी जाट कांग्रेस के साथ तभी तक थे, जब मदेरणा, मिर्धा, ओला, नटवर सिंह जैसे दिग्गज पार्टी की अग्रिम पंक्ति में हुआ करते थे, अब कांग्रेस में ऐसा मजबूत जाट नेता एक भी नहीं है।**

जयपुर, 2 मार्च (का.प्र.)। राजस्थान में इस बार कांग्रेस सरकार वर्गों के आधार पर बोर्ड, निगम, आयोग बनाने के बजाय सीधे जातीय बोर्डों का गठन कर रही है, ताकि उन जातियों को साधा जा सके जो कांग्रेस के साथ सहज नहीं हैं। इसी को ध्यान रखते हुए कांग्रेस सरकार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य नेताओं की मांग पर राजस्थान में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।

इधर कहा जा रहा है कि 5 मार्च को राजधानी जयपुर में होने वाले जाट महाकुंभ से पहले प्रदेश की गहलोत सरकार ने जाट समाज को लेकर एक बड़ा दांव खेला है। गहलोत सरकार ने जाट समाज की प्रमुख मांगों में शामिल वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया है। राज्य सरकार ने किसान समाज की स्थिति का जायजा लेने, प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मलभूत सुविधा उपलब्ध कराने और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव के उद्देश्य से इस कल्याण बोर्ड का गठन किया है। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में 9 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य शामिल हैं. इस बोर्ड में उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण पंचायत राज विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, देवस्थान विभाग, पर्यटन कला संस्कृति विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव सरकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

वैसे जानकारों का कहना यह है कि कांग्रेस विधायक एवं पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से ओबीसी वर्गीकरण को लेकर लगातार अपनी ही राज्य सरकार पर हमलावर हैं, वैसे ही आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल भी इसी मांग को सरकार से लगातार उठाते रहे हैं। सरकार ने वीर तेजा कल्याण बोर्ड का गठन करके इन नेताओं को भी शांत करने का प्रयास किया है। हालांकि सिर्फ वीर तेजा कल्याण बोर्ड बना दिए जाने से जाट समाज या किसान वर्ग कांग्रेस के साथ आ जाएगा, इसमें बहुत लोगों को संशय नजर आता है।

कहा जा रहा है कि किसी समय पूरा जाट समाज कांग्रेस के हुआ करता था। इसका कारण यह था कि तब कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में परसराम मदेरणा, रामनिवास मिर्धा,नाथूराम मिर्धा, नटवर सिंह, शीशराम ओला, नारायण सिंह, डॉ. हरिसिंह जैसे खांटी जाट नेता हुआ करते थे। इनके बाद कांग्रेस में लंबे समय से ना तो जाट नेतृत्व को उभारने का प्रयास हुआ और ना कोई ऐसा जाट नेता इस समय कांग्रेस में है, जो पूरे राजस्थान, या कहे कि राज्य के किसी एक संभाग में भी इतना दम रखता हो, जो समाज को पार्टी के साथ ले आए। भले ही वर्तमान में गोविन्द सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन जाट समाज में उनकी पैठ इतनी मजबूत कभी नहीं रही, कि उन्हें जाट नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके। उनसे ज्यादा मजबूत जाट नेता तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष बीकानेर संभाग के रामेश्वर डूडी को माना जाता है।

कांग्रेस की राज्य सरकार ने भले ही जाट समाज को साधने की कोशिश की हो, लेकिन गहलोत सरकार जब तक ओबीसी वर्गीकरण को लेकर अपनी नीति स्पष्ट नहीं करेगी, तब तक जाट समाज कांग्रेस सरकार के साथ जुटेगा, इसमें संशय है। आगामी 5 मार्च को जयपुर में हो रहे जाट महाकुंभ में भी प्रमुख मांग यही है कि ओबीसी की जातियों का वर्गीकरण किया जाए। यह एक ऐसी मांग है जिसे पूरी किया जाना वर्तमान हालातों में संभव नजर नहीं आता।

यह मांग की चर्चा भर होने से राजस्थान में ओबीसी की अन्य जातियां सरकार के खिलाफ बिगुल बजा सकती है। वीर तेजा कल्याण बोर्ड के गठन से जाट समाज कितना खुश है और कांग्रेस पार्टी के साथ कितना सहज हो सकता है, इसका अंदाजा भी 5 मार्च को हो रहे जाट महाकुंभ के बाद ही लग जाएगा।

चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के कार्यकाल के लिए की जाती है।

याचिकाकर्त्ताओं ने मांग की थी कि देश में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का कोलीजियम जैसा सिस्टम होना चाहिए।

जस्टिस के.एम. जोसफ की अध्यक्षता वाली इस बैंच ने इस मुद्दे पर गत 24 नवम्बर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बैंच के अन्य जजों में हैं जस्टिस अजय रस्तौगी, अनिरूद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सी.टी. रविकुमार।

कार और कंटेनर की आमने-सामने की भिड़ंत

हादसे में दंपती सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत

- **हादसा टोंक जिले के देवली नैशनल हाइवे का है, मृतकों में तीन जने एक ही परिवार के थे।**
- **कार में सवार सभी लोग खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे थे।**

टोंक/देवली 2 मार्च, (निसं)। टोंक जिले के देवली नेशनल हाईवे 52 पर देवडावास पैट्रोल पम्प के समीप कंटेनर और कार में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में दम्पत्ति सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। मृतकों में तीन जने एक ही परिवार के हैं।

हादसे में तीन लोग घायल भी हुए हैं, तीनों गंभीर घायलों को जिले के सआदत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर देवली वृत अधिकारी सुरेश कुमार मेघवाल, घाड थाना अधिकारी राधाकिशन मीणा मौके पर पहुंचे। सभी मृतक और घायल खाटू श्याम जी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। कंटेनर और कार के बीच हुआ यह हादसा इतना जबरदस्त था कि, कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। इसमें फंसे लोगों को निकालने के लिए पुलिस और आसपास के लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने मृतकों व घायलों को 108 की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। हादसे में कार सवार मनीष शर्मा पुत्र बंशीलाल शर्मा (45), पत्नी यीशु शर्मा (40), भाई अमित शर्मा(40) निवासी श्यामनगर देवली व कार चालक रवि पुत्र कैलाश रामसर थाना नसीराबाद हाल देवली की मौत हुई है। जबकि हादसे में दीपाली शर्मा पुत्री मनीष शर्मा(22), अंशुल जैन पुत्र पारस कुमार जैन (27) श्याम नगर देवली, निकेश उर्फ निक्की पुत्र रतनलाल (35) निवासी केकडी गंभीर घायल हो गए, उन्हें गंभीर हालत में जिला मुख्यालय के सआदत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां तीनों घायलों का इलाज जारी है।

रॉबर्ट वाड्रा द्वारा बीकानेर में किसानों की जमीनें हड़पने का मुद्दा विधानसभा में गूंजा

लूणकरणसर विधायक सुमित गोदारा के इस आरोप पर सदन में कांग्रेस ने खूब हंगामा किया

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 2 मार्च। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा द्वारा बीकानेर में किसानों की जमीनें हड़पने का मुद्दा गुरूवार को राजस्थान विधानसभा में गूंजा। लूणकरणसर के भाजपा विधायक सुमित गोदारा ने जब वाड्रा पर यह आरोप लगाए तो सदन में जमकर हंगामा हुआ। शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी.कल्ला ने राबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उन्होंने एक प्रतिशत भी गड़बड़ी नहीं की। बल्कि भाजपा के नेताओं ने भूमिहीन बनकर जमीनें ली और घोटाला किया। कल्ला के इन आरोपों पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ समेत तमाम भाजपा विधायक बिफर गए और पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग उठाई। बाद में सभापति राजेन्द्र पारीक ने बीच-बचाव कर पूरा मामला शांत कराया।

सदन में राजस्व और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधायक सुमित गोदारा ने बीकानेर जिले में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया। गोदारा ने कहा कि फायरिंग रैंज की जमीन में घोटाला हुआ, जो किसान फायरिंग रैंज की जमीन से माइग्रेट हुए, उनकी जमीन को लोगों ने कौड़ियों के दाम में खरीदकर करोड़ों रुपये कमाए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली से आकर जमीनें ली, इस मामले में उनका नाम ईडी में आया है।

सुमित गोदारा के आरोप पर शिक्षा मंत्री बी.डी.कल्ला ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जो सदन का मैंबर नहीं, उसका नाम लेना गलत है। इस पर गोदारा ने कहा कि अंबानी-अडाणी भी सदन के मैंबर नहीं है, उन पर तो आप खूब आरोप लगाते हो।

मंत्री कल्ला ने कहा, जिन्होंने जमीनें ली है, उनमें उनमें अधिकांश लोग बीजेपी के हैं। भाजपा के लोगों ने 5 से 10 हजार बीघा की जमीनों को लाखों रुपये में बेचा। गड़बड़ भाजपा के लोगों ने की है। वाड्रा ने चेक से पेमेंट किया, रजिस्ट्री हुई है उसका पूरा पैसा दिया है।

उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कल्ला पर पलटवार करते हुए कहा, मंत्रीजी ने जिस शख्स का नाम लेकर कहा, वह सारा मामला कोर्ट में चल रहा है। मेरी मांग है सरकार एक कमीशन बना दे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मंत्रीजी, चोर की दाढ़ी में तिनका है। वाड्रा ने बीकानेर जिले में जमीन नहीं खरीदी है, यह साबित कर दो, गलत हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अन्यथा आप दे देना। यह मेरा चैलेंज है।

जिस पर कल्ला ने कहा, वाड्रा ने भूमिहीन बनकर जमीन नहीं ली, भूमिहीन बनकर भाजपा के लोगों ने जमीन ली। वाड्रा ने चेक से पेमेंट दिया है, रजिस्ट्री का पूरा पैसा दिया है। जबकि भाजपा के लोगों ने नकद में जमीनें खरीदी।

उनकी तकरार के बीच सुमित गोदारा ने कहा, आपको पता था कि यहां सोलर प्लांट आने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले जमीन ली, यह तो भ्रष्टाचार हुआ है। महाजन फायरिंग रैंज में माइंस वाली जमीन ली गई। कोलायत के विधायक और मंत्री ने भी वहां जमीन ली है। कल्ला ने कहा कि मेरी तो एक बीघा जमीन भी नहीं है। इस पर गोदारा ने कहा, आप नहीं आपके साथी मंत्री ने खरीदी है। सारे आवंटन की जांच करवा लीजिए। फील्ड फायरिंग रेंज में आपके कोलायत वाले मंत्री को जमीन आवंटित हुई या नहीं हुई। सत्ता पक्ष और भाजपा विधायकों के बीच सदन में बढ़ती तकरार के बाद सभापति राजेन्द्र पारीक ने बीचबचाव कर पूरा मामला शांत कराया।

- **शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा, सदन का जो मैंबर नहीं, उनका नाम लेना गलत है। जिस पर गोदारा ने कहा, अंबानी-अडाणी भी इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम तो आप खूब लेते हो।**
- **इस विवाद के बीच मंत्री कल्ला ने रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट देते हुए कहा कि, उन्होंने एक प्रतिशत भी गड़बड़ी नहीं की, बल्कि भाजपा के नेताओं ने भूमिहीन बन कर जमीने लीं और घोटाला किया।**
- **इस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा, "मंत्रीजी पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। सरकार एक कमीशन बना दे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका है। वाड्रा ने बीकानेर जिले में जमीन नहीं खरीदी है, यह आप साबित कर दो, गलत हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अन्यथा आप दे देना। यह मेरा चैलेंज है।"**

जो कभी कांग्रेस की छत्र...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की स्थिति में न आ सके। लेकिन कांग्रेस छोड़कर जाने वाले लोग भी फायदे में नहीं रहे हैं। वे केवल अपनी मौजूदगी ही दर्शाने की स्थिति तक सीमित रह गये हैं। क्योंकि टी.एम.सी. का प्रदर्शन कुल मिलाकर दयनीय ही रहा है। राज्य विधान की सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद, टी.एम.सी को उन चन्द सीटों में से कुछ ही सीटें मिल पाई हैं, जो पहले कांग्रेस के कब्जे में थी। अन्य स्थान पर टी.एम.सी. एकदम साफ हो गई है तथा राज्य में अपना राजनैतिक अस्तित्व स्थापित नहीं कर सकी है। नागालैंड़ में कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह सफाया हो गया है तथा वह एक भी सीट नहीं जीत पायी है।

पूर्वोत्तर के राज्यों में उभर कर आई एक अन्य विशिष्ट बात वामपंथी दलों की घोर पराजय रही है। इसका पुराना गढ़ त्रिपुरा अब भाजपा तथा अन्य दलों के कब्जे में है। ये दल कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे लेकिन उसके बावजूद, ये 2 साटों पर सिमट गये। अगर इन चुनाव परिणामों को किसी भी रूप में अगले आम चुनावों का संकेतक मान लिया जाये, तो कांग्रेस तथा अन्य सभी दलों को बहुत कुछ सोचना-विचारना होगा जमीनी स्तर पर आमजन को प्रभावित करने के लिये, इन दलों को नई रणनीतियाँ तथा नये विषय तलाशने होंगे।

रूस की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नम्बर पर रहे लोएस्ट बिडर में मैच कर जाती तो शेष 80 ट्रेनों का ठेका दूसरे नम्बर वाले (एल-2) को दे दिया जाएगा। अगर एल-2 कॉन्ट्रेक्ट लेने से इन्कार का देता है तो ऑफर तीसरे लोएस्ट बिडर को दे दिया जाएगा। इस केस में तीसरा लोएस्ट बिडर सिमन्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी.ई.एम.एल.) है। यदि कोई भी बोलीदाता एल-1 द्वारा कोट की गई प्राइस से मैच करने में विफल रहता है तो पूरा कॉन्ट्रेक्ट ही एल-1 को दे दिया जाएगा। अस्सी ट्रेन्स की दूसरी खेप का निर्माण चैन्नई स्थित आई.सी.एफ. संयंत्र से किए जाने की योजना है।

रेल एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर आशंकित हैं कि रूस की टी.एम.एच. वर्ष 2024-25 तक 400 वन्दे भारत ट्रेन्स की डिलीवरी नहीं दे पाएगी। आई.सी.एफ. के पूर्व महाप्रबन्धक सुधांशु मणि ने बताया कि "यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण यूरोप के मल्टीनैशनल मैन्यूफैक्चरर्स द्वारा रूस की कम्पनी का सहयोग करने की उम्मीद नहीं है।

यदि टी.एम.एच. को कॉन्ट्रेक्ट मिलता है तो उसे भारत की स्थानीय कम्पनियों पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना होगा, हालांकि यह स्थिति भारतीय उद्योग जगत के लिए अच्छी होगी, लेकिन इसमें बड़ी चुनौतियां भी हैं।" सी.जे.एस.सी. ट्रांसमैशहोल्डिंग के बुल्गारिया, बेलारूस, इजिप्ट, कज़ाकिस्तान और सर्बिया सहित अन्य देशों में ग्राहक हैं, लेकिन भारत में अब तक उसकी उपस्थिति नहीं रही है।

अडानी विवाद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कामथ, नंदन नीलेकनी और सोमशेखर सुन्दरेसन भी होगें।

दिल्ली के एडवोकेट एम.एल. शर्मा, एडवोकेट विशाल तिवारी, मध्यप्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर और अनामिका जायसवाल द्वारा दायर कुछ याचिकाओं पर जीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) डी. वाय चन्द्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की एक बैंच ने अपना आदेश पारित किया।

आदेश में कहा गया कि एक्सपर्ट कमेटी शेयर बाजार को अस्थिर करने वाली स्थिति और आकस्मिक कारकों को लेकर एक समग्र आकलन प्रस्तुत करेगी।

उसमें आगे कहा गया कि कमेटी निवेशकों में जागरूकता पैदा करने के उपाय सम्भाएगी और यह जांच भी करेगी कि अडानी ग्रुप का अन्य कम्पनियों के संदर्भ में शेयर बाजारों से सम्बन्धित कानूनों के कथित उल्लंघन में क्या कोई नियामक कमियां रही हैं।

कांग्रेस ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अडानी मे मुद्दे की सच्चाई को सामने नहीं ला पायेगा। उन्होंने कहा कि 13 मार्च को जब संसद की बैठके पुन: शुरू होंगी, उस समय कांग्रेस जे.पी.सी. की माँग फिर से उठायेगी। इस बात पर जो देते हुये कि उन्होंने यह बात पहले भी कही थी, जयराम रमेश ने पत्रकारों से कहा, "अगर प्रधानमंत्री तथा सरकार को जवाबदेह ठहराना है तो जे.पी.सी.

- **कांग्रेस ने कहा, अडानी विवाद की जांच जे.पी.सी. द्वारा ही की जानी चाहिए। जे.पी.सी. ही गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबंधों की सच्चाई पता लगाएगी।**

के अलावा अन्य कोई भी कमेटी नरेन्द्र मोदी को विधि सम्मत तथा निर्दोष ठहराने के अलावा और कुछ नहीं करेगी।" रमेश ने कहा, "अडानी के प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी केवल सेबी के नियम और कानून के अल्लघंनों की जाँच तक ही सीमित है। अगर जे.पी.सी. गठित नहीं होती है तो प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के बीच के रिश्ते की सच्चाई कमी भी सामने नहीं आयेगी।"

मतभेदों के साये में जी-20 की बैठक

- **मतभेदों के कारण जी-20 बैठक के बाद विदेश मंत्रियों का जॉइन्ट फोटो सैशन नहीं हो पाया।**

नयी दिल्ली 2 मार्च (वार्ता)। जी-20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन रूस संघर्ष को लेकर देशों के बीच एक साझा रुख पर आम सहमति नहीं बन पायी लेकिन उन्होंने इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों पर पड़ने वाले आर्थिक दुष्प्रभावों एवं उनके समाधान की जरूरत पर सहमति व्यक्त की।

इस स्थिति में बैठक में भारत ने अपनी अध्यक्षीय भूमिका में ग्लोबल साउथ की आवाज़ को पुरज़ोर तरीके से उठाया।

बैठक में संयुक्त वक्तव्य के एक 24 बिन्दु वाले दस्तावेज के मसौदे पर यूक्रेन रूस संकट के बारे में उल्लेख को लेकर पूर्ण सहमति कायम नहीं हुई जिसे अध्यक्षीय निष्कर्ष दस्तावेज़ के रूप में इस नोट के साथ जारी किया गया कि बिन्दु 3 एवं 4 को छोड़कर सभी बिन्दुओं पर सभी विदेश मंत्री सहमत हैं। बिन्दु 3 एवं 4 में यूक्रेन रूस संघर्ष के बारे में टिप्पणी की गयी है।

'आई एम सॉरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची लालसोट थाना पुलिस ने फंदे से झूल रही छात्रा को जिला अस्पताल ले गई, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मैडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया एवं केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

थानाधिकारी नाथू लाल मीणा ने बताया कि निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा खुशबू मीणा ने मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा है जो पुलिस को प्राप्त हुआ है उसके आधार पर सुसाइड से जुड़ी घटना की कानूनी जांच पड़ताल की जा रही है।

वहीं ज्यादा अंक लाकर ज्यादा प्रतिशत बनाने की भागम भाग में एक छात्रा द्वारा खुद को असमर्थ बताते हुए सुसाइड करने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। यह ऐसा पहला मामला नहीं है कि किसी विद्यार्थी ने पढ़ाई के दबाव में आकर सुसाइड किया हो। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

तमिलनाडू के उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है, जैसा कि उपचुनावों में अक्सर होता है, मानो तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल का जीतना कोई अहम बात न हो।

अन्नाद्रमुक तथा उसके गठबंधन पार्टनरों के लिये यह बिन्दु चिन्तित करने वाला होना ही चाहिये कि एक ऐसे क्षेत्र में, जो अन्नाद्रमुक का परम्परागत गढ़ रहा हो, मतगणना के कुछ राउण्ड शेष रहते, कांग्रेस उम्मीदवार की बढ़त 50,000 का आँकड़ा पार कर गई थी। भाजपा का कहना है कि तमिल मतदाताओं ने द्रमुक की बातों पर भरोसा किया।

यह स्पष्ट होने के शीघ्र बाद कि कांग्रेस प्रत्याशी आसानी से जीत रहा है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तथा डी.एम.के. प्रमुख एम.के. स्टालिन ने इस जीत का श्रेय विकास और ग्रोथ के "द्रविड़ मॉडल" को दिया तथा कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों तक इस मॉडल निरन्तर प्रदर्शित होता रहेगा।

उन्होंने कहा कि अब 2024 के लोक सभा चुनावों में डी.एम.के. के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन की जीत की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। स्टालिन ने कहा, "प्रचार के दौरान, मैने बार-बार शासन के द्रविड़ मॉडल के लिये जनता का समर्थन माँगा था। जनता ने यह कहते हुये अपना फैसला दिया है कि यह और अधिक ऊर्जा के साथ होना चाहिये।"

स्टालिन ने विपक्षी नेताओं की पूरी जमात को दिये एक संदेश में कहा "अब समय आ गया है कि प्रत्येक पार्टी यह भूल जाये कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है तथा एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर चुनाव लड़े।" उन्होंने कहा "यह देखना महत्वपूर्ण है कि कौन नहीं जीतना चाहिये तथा कौन प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिये।"

प्रसंगवश बता दें कि एक दिन पूर्व उनके जन्मदिन के अवसर पर एकत्रित भीड़ में, विपक्ष के बहुत से नेता चेन्नई में उपस्थित थे। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष की कोई भी ग्रुपिंग कांग्रेस के बिना सम्भव नहीं है।

वहाँ इकठ्ठे हुये नेताओं का आम सोच यह था कि जो पार्टियाँ यह कह रही है कि वे कांग्रेस और भाजपा से बराबर दूरी पर हैं, विपक्षी एकता की दुश्मन हैं तथा जान बूझकर या बिना सोचे-समझे, वे भाजपा की सत्ता वापसी में मदद करेंगी।

स्टालिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने पार्टी और सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत की है तथा "द्रविड़ हितों" के पोषक छवि अर्जित की है। उनकी यह छवि उस समय बहुत काम आती है, जब जनता की नज़रें दूसरी द्रविड़ पार्टी अन्नाद्रमुक पर जाती है, जो भाजपा द्वारा संचालित दिखाई देती है।

एक कांग्रेस नेता ने भाजपा के इस आरोप, यह जीत द्रमुक के धन-बल के प्रदर्शन का परिणाम है, पर प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि द्रमुक और कांग्रेस तमिलनाडु से सभी 40 सीटें (जिनमें पुडुचेरी लोकसभा सीट भी शामिल है) जीतेंगी इसमें कोई संदेह नहीं हैं।

इस कांग्रेस नेता ने कहा, "भाजपा के साथ केन्द्र सरकार है तथा विभिन्न जाँच एजेंसियाँ हैं, चुनाव आयोग है। भाजपा इन एजेंसियों की शिकायतों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही, मीडिया में इन पर आरोप क्यों नहीं लगा रही। विजयी रहे कांग्रेस प्रत्याशी ई.वी.के.एस. एलनगोवन ने कहा कि वस्तुत: "अन्नाद्रमुक तथा भाजपा पिछले कुछ दिनों से अन्धाधुन्ध आरोप लगाये जा रही थी क्योंकि वे जानती थी कि वे उप चुनाव में बुरी तरह से पराजित होने वाली हैं। इसलिये वे इस समय जो कुछ कह रहे हैं, उसमें अचम्भित होने जैसी कोई बात नहीं हैं।"

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्पाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908